

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

—:—

क0 544 / 59 / 18 / ब-1 / चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04 / 05 / 2018

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नर्मदा घाटी विकास, जल संसाधन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, भोपाल ।

विषय:—वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम त्रैमास में पूंजीगत व्यय सीमा का निर्धारण।

संदर्भ:—इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 445 / 587 / 17 / ब-1 / चार भोपाल,
दिनांक 09 / 04 / 2018 एवं 467 / 587 / 17 / ब-1 / चार भोपाल,
दिनांक 20 / 04 / 2018 ।

संदर्भित पत्रों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मासिक / त्रैमासिक व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। निर्माण विभागों के अंतर्गत पूंजीगत व्यय हेतु प्रथम त्रैमास के माह मई 2018 हेतु निम्न तालिका अनुसार सीमा निर्धारित की जाती है :-

(राशि करोड़ रु.में)

स. क.	विभाग का नाम	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	माह मई हेतु निर्धारित सीमा
1	2	3	4	5
1	नर्मदा घाटी विकास (सरदार सरोवर परियोजना को छोड़कर)	48	4700	450
2	जल संसाधन	23,45	4700,4701,4702,4705	750
3	लोक निर्माण	24,67	4059,5054, 4216	750
4	लोक स्वा.यांत्रिकी	20	4215	300

2. कण्डिका 1 के तारतम्य में वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 467 / 587 / 17 / ब-1 / चार, दिनांक 20 / 04 / 2018 के प्रावधान लागू नहीं होंगे तथा विभाग तालिका के कॉलम 5 में निर्धारित सीमा तक व्यय कर सकेंगे। विभागों को इस व्यय सीमा के अन्तर्गत योजनावार सीमा तय करने के अधिकार होंगे।

निरन्तर.....

//2//

3. राज्य शासन के कोष से देयक/चेक्स के आहरण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एल 1-10/832/2017/ब-7/डीएमसी /चार, दिनांक 10/04/2018 यथावत लागू रहेगा।

04/5/18

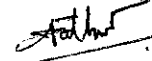
(अजीत कुमार)

संचालक बजट एवं सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

क0545/59/18/ब-1/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 04/05/2018

आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।



अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग